

केन-बेतवा लकि परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत केन-बेतवा लकि परियोजना (उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश) को लागू करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा एक संचालन समिति एवं केन-बेतवा लकि परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) का गठन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस 20 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता इसके सदस्य सचिव होंगे।
- संचालन समिति समझौता ज्ञापन के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, केबीएलपीए के लिये मौलिक प्रशासनिक नीतियों, उपनयनों और मानदंडों को मंजूरी देगी, अपने वार्षिक बजट, वित्तीय विवरणों को मंजूरी देने और जाँचने के अलावा अपने दायित्वों एवं ऋण संबंधी प्रस्तावों पर नरिणय लेगी।
- सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, केन-बेतवा लकि परियोजना प्राधिकरण दौधन बांध, बजिली घर, केन-बेतवा लकि जल वाहक नहर, सुरंग, लोअर परियोजना, कोटा बैराज तथा बनिा कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना के नष्पादन के लिये ज़म्मेदार होगा।
- केबीएलपीए का नेतृत्व भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर के एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- केन-बेतवा लकि परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 ज़िले आते हैं। इनमें मध्य प्रदेश के 9 ज़िले- पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, वदिशा, शविपुरी और रायसेन शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बाँदा, महोबा, झाँसी और ललतिपुर ज़िले हैं।
- इस पूरी योजना से इन सभी ज़िलों की करीब 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर सचिाई हो सकेगी और 62 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मलि सकेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट भी बनाया जाएगा।